

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल
अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3251-पीबीआर/14 विरुद्ध आदेश दिनांक 26-2-14 पारित द्वारा तहसीलदार तहसील धार प्रकरण क्रमांक 18/अ-6/2010-11 नया प्रकरण क्रमांक 31/अ-6/2013-14.

करणसिंह पिता हिन्दुसिंह
निवासी ग्राम नवासा
तहसील व जिला धार

.....आवेदक

विरुद्ध

- 1- अजय पिता चोखेलाल चौहान
निवासी ग्राम नौगांव
तहसील व जिला धार
- 2- जसवंतसिंह पिता करणसिंह
निवासी ग्राम नवासा
तहसील व जिला धार

.....अनावेदकगण

श्री दिवाकर दीक्षित, अभिभाषक, आवेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 16/2/12 को पारित)


आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार तहसील धार द्वारा पारित आदेश दिनांक 26-2-14 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा अनावेदक क्रमांक 2 के भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से कय किये जाने के आधार पर अनावेदक क्रमांक 2 के स्थान पर अनावेदक क्रमांक 1 का नाम दर्ज किये जाने संबंधी संहिता की धारा 109, 110 के अंतर्गत नामांतरण हेतु आवेदन पत्र तहसीलदार, धार के समक्ष प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा प्रकरण क्रमांक 18/अ-6/2010-11 नया प्रकरण क्रमांक 31/अ-6/2013-14 दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई । कार्यवाही

के दौरान आवेदक द्वारा आपत्ति आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने पर तहसीलदार द्वारा दिनांक 26-2-14 को आदेश पारित कर आवेदक की आपत्ति निरस्त की गई । तहसीलदार के इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा अभिलेख के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने का अनुरोध किया गया, अतः प्रकरण का निराकरण अभिलेख के आधार पर किया जा रहा है । निगरानी में मुख्य रूप से यह आधार लिया गया है कि प्रश्नाधीन भूमि का आवेदक भूमिस्वामी है, इसलिए अनावेदक क्रमांक 2 को भूमि विक्रय करने का अधिकार नहीं था । यह भी आधार लिया गया है कि प्रश्नाधीन भूमि आवेदक के नाम भूमिस्वामी स्वत्व पर दर्ज है, और उसके जीतेजी प्रश्नाधीन भूमि पर जसवंतसिंह का कोई अधिकार नहीं है । अंत यह आधार लिया गया है कि तहसीलदार द्वारा व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 1 नियम 10 सहपठित धारा 151 का आवेदन पत्र को समझने में भूल की गई है, क्योंकि आवेदक प्रश्नाधीन भूमि का भूमिस्वामी होकर हितबद्ध पक्षकार है ।

4/ आवेदक के विद्वान अभिभाषकों द्वारा निगरानी में उठाये गये तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय के समक्ष प्रकरण अभी विचाराधीन है, और उनके द्वारा प्रकरण का अंतिम निराकरण किया जाना है । अतः यदि प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक को किसी प्रकार का कोई स्वत्व प्राप्त है तो वे तहसील न्यायालय में स्वत्व के संबंध में प्रमाण/साक्ष्य प्रस्तुत कर सकते हैं । आवेदक की ओर से प्रमाण/साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए तहसीलदार आवेदक को एक अवसर उपलब्ध कराये तथा प्रकरण के अंतिम निराकरण के समय आवेदक की ओर से प्रस्तुत प्रमाण/साक्ष्य पर विचार कर उनके संबंध में निर्णय लें। उपरोक्त निष्कर्ष के साथ यह निगरानी समाप्त की जाती है ।



(मनोज गोयल)

अध्यक्ष

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर